



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 61 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)

1 फरवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 नवम्बर, 2017

संख्या- 14/भा०स०प०-17-08/08 का० 11305 -- चूँकि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक 10 जून, 2002 द्वारा झारखण्ड राज्य में क्रीमीलेयर की पहचान के लिए भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या-36012/22/93 दिनांक 8 सितम्बर, 1993 की अनुसूची को यथावत अंगीकृत करते हुए क्रीमीलेयर के निर्धारण की क्राईटेरिया को पूर्णरूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जापन संख्या-36033/1/2013-स्था० (आरक्षण) दिनांक 13 सितम्बर, 2017 द्वारा कार्यालय जापन दिनांक 8 सितम्बर, 1993 की अनुसूची की कंडिका-VI में आय के मानदंड को संशोधित करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग (ओ०बी०सी०) के सदस्यों को सामाजिक

रूप से उन्नत व्यक्तियों/सम्पन्न वर्गों के रूप में आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड को 6 लाख रूपए से बढ़ाकर 8 लाख रूपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है ।

एतदर्थ संकल्प संख्या-3482 दिनांक 10 जून, 2002 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के सदस्यों में से क्रीमीलेयर के निर्धारण हेतु आय का मानदंड अब 6 लाख रूपए से बढ़कर 8 लाख रूपए प्रति वर्ष हो जाएगा ।

उक्त निर्णय सर्व साधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित की जा रही है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव ।
